Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding problems of people displaced due to acquisition of their land by Coal India-laid.

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): कोलियरियों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोलियरी विस्तार के लिए कोल इंडिया (भारत सरकार) एवं राज्य सरकार के द्वारा रैयतों की जमीन का अधिग्रहण समय-समय पर किया गया है । ढोरी, बी.एण्ड. के एवं कथारा क्षेत्र में कुछ रैयतों को नियोजन और मुआवजा दिया गया है, लेकिन ज्यादातर रैयतों के मामले लंबित हैं । रैयतों द्वारा आंदोलन आए दिन होते रहते हैं, लेकिन प्रबंधन समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है । सीएसआर फंड से विस्थापित गाँवों के लिए विकास के लिए जो पैसा सी.सी.एल., मुख्यालय से आता है वो भी प्रबंधन अन्यत्र या अपनी कॉलोनियों में खर्च कर देते हैं । अब तक विस्थापित परिवारों को रोजगार, मेडिकल कार्ड, विस्थापित प्रमाण-पत्र की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे इस विषय का स्थायी समाधान हो सके । आर आर पॉलिसी के नाम से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, घने जंगलों को उजाड़ा जा रहा है । विस्थापित लोग प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर हो गए हैं और प्रबंधन प्रदूषण कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है ।

कृपया, इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और विस्थापितों की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु एक कमेटी बनाई जाए, जो इन विषयों को देखे और साथ ही अवैध उत्खनन और प्रदूषण जैसी समस्याओं को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : यदि, हमने नड्डा जी की बात को गलत तरीके से पेश किया है और जब नड्डा जी नहीं हैं, तो आप कैसे उनके पक्ष को रख सकते हैं? ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं आपको बता देता हूं । ...(व्यवधान) आप बैठ जाइए । मैं वक्तव्य नहीं दे रहा था । मैं नियम-357 के तहत स्पष्टीकरण दे रहा था । मैं उनकी कही हुई बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूं । इसलिए, नड्डा जी के नाम का मैंने जिक्र नहीं किया है । उन्होंने गलत जिक्र किया है । मैंने उसी को मेंशन किया है । ...(व्यवधान)